ई संदेश

09 जुलाई, 2026 | अंक - 213

सात दिन, सात पृष्ठ

आम महोत्सव-2026

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फैसला: दिव्यांगजन का भरण-पोषण अनुदान बढ़ा, व्यवस्थाएं होंगी और सुदृढ़
- सकारात्मक सोच और टीम वर्क ही विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्तिः मुख्यमंत्री
- वैश्विक ब्रांड बनेगा उत्तर प्रदेश का आम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- उत्तर प्रदेश के हर जिले में सुदृढ़ होंगी कैंसर उपचार सुविधाएं शुरू होगा एकीकृत 'यू0पी0टी0ई0एन0' नेटवर्क
- आस्था, तकनीक और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: प्रयागराज में साकार हो रहा 'स्मार्ट सिटी' का विजन
- प्रतापगढ़ को मिली ₹384 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात विरासत और समृद्धि का बना आधार
- सुलतानपुर में विकास का नया अध्याय: मजबूत कनेक्टिविटी से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम
- शिक्षकों को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा: सीएम योगी ने शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना
- शस्त्र और शास्त्र के संधान का केंद्र बनेगा चित्रकूट, ₹951 करोड़ की विकास परियोजनाओं से संवरेगी प्रभु श्रीराम की तपोभूमि
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 जुलाई 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा फैसला: दिव्यांगजन का भरण-पोषण अनुदान बढ़ा, व्यवस्थाएं होंगी और सुदृढ़

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 02 जुलाई, 2026 को अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। लोक-कल्याण को समर्पित उत्तर प्रदेश सरकार के विजन के अनुरूप, मुख्यमंत्री जी ने इस बैठक में मानसिक मन्दित एवं निराश्रित दिव्यांगजन के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए एक अत्यंत संवेदनशील और बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने प्रदेश के आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों एवं हाफ वे होम में रहने वाले संवासियों के भरण-पोषण हेतु दी जाने वाली प्रति संवासी अनुदान राशि को 2,000 रुपये से सीधे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की।

इस ऐतिहासिक निर्णय के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने अत्यंत संवेदनशीलता के साथ रेखांकित किया कि आश्रय गृहों में निवास करने वाले मानसिक मन्दित एवं निराश्रित दिव्यांग भाई-बहन पूरी तरह से संस्थागत देखभाल और सहयोग पर निर्भर होते हैं। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ-साथ अत्यंत पौष्टिक भोजन, समुचित स्वास्थ्य देखभाल और एक गरिमापूर्ण जीवन की समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की परम जिम्मेदारी है। समय के साथ आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती लागत को व्यावहारिक रूप से देखते हुए संवासियों के भरण-पोषण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सुचारू बनाया जाना समय की मांग थी, जिसे सरकार ने सहर्ष पूरा किया है।

मुख्यमंत्री जी ने दृढ़तापूर्वक कहा कि दिव्यांगजन के सम्मान, सुरक्षा और गरिमापूर्ण जीवन को सुनिश्चित करने से जुड़े प्रत्येक प्रयास को उत्तर प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में नियमित अंतराल पर पूरी पारदर्शिता के साथ दिव्यांगजन सहायक उपकरण वितरण शिविरों का भव्य आयोजन किया जाए। इन शिविरों के माध्यम से सभी पात्र दिव्यांगजन को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले कृत्रिम अंग एवं आधुनिक सहायक उपकरण पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएं।

बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने विशेष निर्देश दिए कि श्रवण बाधित बच्चों का बेहद शुरुआती स्तर पर ही शीघ्र चिन्हांकन किया जाए। ऐसे बच्चों के लिए समयबद्ध तरीके से कॉक्लियर इम्प्लाण्ट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और सफल उपचार के उपरान्त उनके पुनर्वास की भी समुचित व्यवस्था की जाए, ताकि वे समाज में एक सामान्य और समर्थ नागरिक की तरह आगे बढ़ सकें। राज्य सरकार का स्पष्ट उद्देश्य दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की जनहितैषी योजनाओं के जरिए हर दिव्यांगजन को सम्मानजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन की मुख्यधारा से जोड़ना है।

प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन के सामाजिक, आर्थिक, चिकित्सकीय, भौतिक एवं शैक्षिक पुनर्वास से जुड़ी समस्त कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में राज्य के विशेष विद्यालयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विशेष रूप से प्रशिक्षित मानव संसाधन, अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं तथा समस्त शासकीय भवनों में बाधारहित सुगम्य वातावरण विकसित करने के कार्यों को विशेष प्राथमिकता के साथ तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। विशेष विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को उत्कृष्ट बनाने के लिए रिक्त पदों पर शिक्षकों की समयबद्ध और पारदर्शी तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो।

समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा संचालित लोक-कल्याणकारी उपलब्धियों के शानदार आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए। प्रदेश में दिव्यांग पेंशन योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना, शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार, और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में शत-प्रतिशत निःशुल्क यात्रा जैसी अनेक योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 12,23,295 दिव्यांगजन को पेंशन योजना से सीधे लाभान्वित किया गया, जबकि 34,420 पात्र लाभार्थियों को 43,689 अत्याधुनिक सहायक उपकरण वितरित किए गए। इसी अवधि में 226 श्रवण बाधित बच्चों का सफल कॉक्लियर इम्प्लाण्ट कराया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में भी अब तक 68 जनपदों से 335 बच्चों का सफलतापूर्वक चिन्हांकन किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश सरकार के विकासपरक प्रयासों का ही प्रतिफल है कि वर्ष 2017 तक प्रदेश के मात्र 10 जनपदों में संचालित होने वाले बचपन डे-केयर सेण्टर आज बढ़कर 25 जनपदों में सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तथा 28 अन्य जनपदों में इनकी स्थापना की प्रक्रिया युद्धस्तर पर प्रगति पर है। इसी प्रकार, वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 16 विशेष विद्यालय संचालित थे, जिनकी संख्या को वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 28 कर दिया है। इन सभी आधुनिक विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित छात्रावास, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक सहायक उपकरण जैसी सभी विश्वस्तरीय सुविधाएं सरकार द्वारा पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सकारात्मक सोच और टीम वर्क ही विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 जुलाई, 2026 को सी.जी. सिटी में लगभग 464.15 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 'डॉ। राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी' के अत्याधुनिक नवीन परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान को देश के अग्रणी 'स्कूल ऑफ पब्लिक लीडरशिप' के रूप में विकसित करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता, सकारात्मक सोच और टीम वर्क ही विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति है। विगत 9 वर्षों में राज्य ने सुशासन और पारदर्शिता के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था 'पॉलिसी पैरालिसिस' से मुक्त होकर परिणाम आधारित कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने रेखांकित किया कि वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश की छवि नकारात्मक थी, लेकिन मजबूत प्रशासनिक इच्छाशक्ति से आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकलकर देश की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने की ओर अग्रसर है और लगातार 6 वर्षों से रेवेन्यू सरप्लस राज्य बना हुआ है।

तकनीक आधारित सुशासन की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीबीटी, ई-पॉस और जनधन-आधार-मोबाइल की त्रिशक्ति से सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। गन्ना किसानों के लिए लागू ई-गन्ना प्रणाली और पारदर्शी तौल व्यवस्था ने उनकी पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान किया है।

मुख्यमंत्री जी ने बताया कि देश के 60 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे आज उत्तर प्रदेश में हैं। मजबूत सड़क नेटवर्क, मेट्रो, रैपिड रेल और अयोध्या व नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी बुनियादी परियोजनाएं डबल इंजन सरकार की विकास प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।

अंत में उन्होंने कहा कि विजन को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र की है। जनता की सहभागिता से तैयार विजन डॉक्यूमेंट के लिए मिले 98 लाख सुझावों की सराहना प्रधानमंत्री जी ने भी की है। यह नया परिसर आधुनिक ट्रेनिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है, जहां एक साथ 300 आवासीय और कुल 900 प्रशिक्षुओं को उत्कृष्ट प्रशिक्षण देना संभव होगा।

वैश्विक ब्रांड बनेगा उत्तर प्रदेश का आम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश आम महोत्सव-2026 का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रगतिशील बागवानों को सम्मानित किया, स्मारिका का विमोचन किया और विदेशों में निर्यात होने वाले आम के वाहनों को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है और यह महोत्सव हमारे अन्नदाता किसानों को वैश्विक पहचान दिलाने का एक सशक्त मंच है।

मुख्यमंत्री जी ने गर्व के साथ बताया कि अब मलिहाबाद के प्रसिद्ध दशहरी आम को जीआई (GI) टैग प्राप्त हो गया है, जिससे यह एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। राज्य सरकार ने मलिहाबादी आम को 'काकोरी' नाम से एक नया ब्रांड दिया है, जो देश के अमर शहीदों को समर्पित है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर और अमरोहा में चार आधुनिक पैक हाउस पूरी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं।

किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि पारंपरिक बागवानी को वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट से जोड़ा जाए, तो मुनाफा काफी बढ़ जाता है। सरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के पास एक 'इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट पार्क' का निर्माण करने जा रही है, जिससे प्रदेश के फल और सब्जियां आसानी से विदेशों में भेजी जा सकेंगी।

मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमें उत्तर प्रदेश को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 'मैंगो वैल्यू चेन' का केंद्र बनाना होगा। इसके लिए उद्यान विभाग को ड्रोन, एआई-बेस्ड फार्मिंग और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज राज्य के किसान अपने उत्पादों को यूके, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर और कुवैत जैसे अनेक देशों में सफलतापूर्वक निर्यात कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के हर जिले में सुदृढ़ होंगी कैंसर उपचार सुविधाएं शुरू होगा एकीकृत 'यू0पी0टी0ई0एन0' नेटवर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 03 जुलाई, 2026 को प्रदेश के प्रत्येक जिले तक उच्चस्तरीय कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित करने तथा सड़क दुर्घटनाओं व अन्य आपात स्थितियों में 'गोल्डन आवर' के भीतर त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के लिए प्रदेशव्यापी एकीकृत ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क स्थापित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विशेषज्ञों के साथ आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य कैंसर टास्क फोर्स और उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क (यू0पी0टी0ई0एन0) द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाओं की व्यापक समीक्षा की।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को त्वरित उपचार, समय पर जाँच, आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ मानव संसाधन तथा सुदृढ़ रेफरल प्रणाली पर आधारित बनाने पर विशेष बल दिया, ताकि प्रत्येक नागरिक को उसके निकट ही गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को दोनों ही महत्वपूर्ण प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण कर चरणबद्ध, समयबद्ध और परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करने के लिए निर्देशित किया। सरकार का विजन राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को केवल उपचार केंद्रित न रखकर रोकथाम, शीघ्र पहचान, गुणवत्तापूर्ण उपचार, पुनर्वास, अनुसंधान तथा तकनीक आधारित समन्वित प्रणाली के रूप में विकसित करना है।

बैठक में मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक मण्डल में आधुनिक कैंसर केन्द्र स्थापित करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक नियमित कैंसर स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने को कहा। तम्बाकू जनित कैंसर की रोकथाम के लिए प्रभावी जनजागरूकता अभियान चलाने और मरीजों की स्क्रीनिंग से लेकर उपचार और फॉलोअप तक की पूरी व्यवस्था को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में अवगत कराया गया कि जागरूकता के अभाव और इलाज में देरी से उत्पन्न गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए इसके लिए वर्ष 2026 से 2036 तक का एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय राज्य कैंसर रोडमैप तैयार किया गया है, जो रोकथाम, स्क्रीनिंग, डिजिटल स्वास्थ्य, पैलिएटिव केयर और अनुसंधान जैसे आठ प्रमुख स्तम्भों पर आधारित होगा। इसके तहत बाल्यावस्था कैंसर के लिए भी सभी प्रमुख केन्द्रों पर समग्र उपचार सुविधा विकसित की जाएगी।

ट्रॉमा एवं आपात चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने 'उत्तर प्रदेश ट्रॉमा एवं इमरजेंसी नेटवर्क' (यू0पी0टी0ई0एन0) के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल रेफरल प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे एम्बुलेंस, चिकित्सकों, बेड की उपलब्धता तथा उपचार सुविधाओं की वास्तविक समय में निगरानी हो सकेगी। इस नेटवर्क के अंतर्गत लेवल-1 एपेक्स केन्द्र, लेवल-2 क्षेत्रीय केन्द्र तथा लेवल-3 जिला एवं प्राथमिक प्रतिक्रिया इकाइयाँ शामिल होंगी। इस सुदृढ़ व्यवस्था के माध्यम से राज्य की लगभग 95 प्रतिशत आबादी को महज 60 मिनट के भीतर विशेषज्ञ आपात चिकित्सा उपलब्ध कराने का दूरदर्शी लक्ष्य रखा गया है, जिससे दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को न्यूनतम किया जा सके।

आस्था, तकनीक और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर: प्रयागराज में साकार हो रहा 'स्मार्ट सिटी' का विजन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 06 जुलाई, 2026 को पावन धरा प्रयागराज के काली घाट पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति पखवाड़ा के अवसर पर भव्य 'प्रेरणा स्थल' का लोकार्पण किया। राष्ट्रनिर्माण को समर्पित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने देश की तीन महान विभूतियों—डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और श्रद्धेय अशोक सिंघल की नगर निगम द्वारा स्थापित भव्य प्रतिमाओं का अनावरण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने लोक-कल्याणकारी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की और यमुना जी में आयोजित 'एकता नौका रेस' को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र, प्रतीकात्मक चेक, सफाई किट तथा आवास की चाबियां सौंपी गईं। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित साइंस लैब के 'क्यूरियोसिटी कॉर्नर स्टॉल' का अवलोकन कर बच्चों से संवाद किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकास के साथ विरासत' के मंत्र को अपनाकर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने प्रयागराज की पौराणिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि नाग वासुकि मंदिर, पातालपुरी, सरस्वती कूप और अक्षय वट मार्ग का जीर्णोद्धार कर डबल इंजन सरकार ने आस्था का गौरव लौटाया है।

प्रयागराज के आधुनिक विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने बताया कि यहाँ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही, गंगा जी पर नए पुल के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और फोर-लेन कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने नगर निगम द्वारा पीपीपी मोड पर 'वेस्ट-टू-वेल्थ' के सिद्धांत पर निर्मित 'शिवालय पार्क' की सराहना करते हुए इसे स्मार्ट सिटी विजन के तहत नागरिकों के लिए 'ईज ऑफ लिविंग' का एक बेहतरीन और प्रेरक मॉडल बताया।

प्रतापगढ़ को मिली ₹384 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात विरासत और समृद्धि का बना आधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 07 जुलाई, 2026 को जनपद प्रतापगढ़ में ₹384 करोड़ से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्होंने प्रतापगढ़ तथा विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹155 करोड़ की 55 परियोजनाओं को जनता को समर्पित किया और ₹228 करोड़ की 56 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, चाबियां, आयुष्मान कार्ड और टूलकिट प्रदान करने के साथ ही बीपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली स्थानीय मेधावी सुश्री श्रद्धा पाण्डेय को आई-पैड देकर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने प्रतापगढ़ की गौरवशाली पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक परंपरा को नमन किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जो जिला कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पिछड़ा माना जाता था, आज वह विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से प्रतापगढ़ में डॉ. सोनेलाल पटेल जी के नाम पर भव्य मेडिकल कॉलेज के बाद अब नर्सिंग कॉलेज की भी सौगात मिल चुकी है। इसके अलावा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माँ बेल्हा भवानी और माँ चंद्रिका देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण तथा गंगा एक्सप्रेस-वे के माध्यम से क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने पूर्ववर्ती सरकारों के 'वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया' के रवैये पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज' और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) की पहचान दी है। ओडीओपी के माध्यम से प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध आंवले को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया गया है। उन्होंने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा को लागू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बिना भेदभाव के हर गरीब को राशन, आवास, और आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी के 'सबका साथ-सबका विकास' के संकल्प को धरातल पर सिद्ध करता है।

सुलतानपुर में विकास का नया अध्याय: मजबूत कनेक्टिविटी से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 07 जुलाई, 2026 को जनपद सुलतानपुर को 819 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 99 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। विधानसभा सुलतानपुर और इसौली से जुड़ी इन परियोजनाओं में राजकीय मेडिकल कॉलेज का भव्य लोकार्पण भी शामिल रहा, जो क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा।

इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, प्रशस्ति पत्र, आवास की चाभियां और थर्मल प्रिंटर जैसी सहायता सामग्री वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूली बच्चों को बैग व पुस्तकें बांटीं और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई तथा बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब एक अच्छी सरकार आती है, तो विकास और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल तैयार होता है। आज प्रदेश में सड़कों का जो शानदार जाल बिछा है, वही कनेक्टिविटी और प्रगति का असली आधार है। जितनी तेज गति से विकास होगा, नागरिकों के जीवन में उतनी ही तेजी से समृद्धि आएगी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' का सपना साकार होगा।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के समय व्याप्त अराजकता, गुंडागर्दी और जमीनों पर अवैध कब्जों की आलोचना करते हुए कहा कि नया उत्तर प्रदेश अब इस व्यवस्था को कतई स्वीकार नहीं करेगा। वर्तमान सरकार ने माफियाओं से 64,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया है, जिस पर अब युवाओं के भविष्य के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जैसी आधुनिक संस्थाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि आज यूपी देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होकर भारत की अर्थव्यवस्था का 'ग्रोथ इंजन' बन चुका है। रोजगार के मोर्चे पर पिछले 9 वर्षों में 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सुलतानपुर की बेहतर रोड कनेक्टिविटी और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बनने वाला इंडस्ट्रियल क्लस्टर यहां के युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर खोलेगा।

अयोध्या धाम से जुड़ी हालिया घटनाओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग नकारात्मक राजनीति के तहत पावन अयोध्या को बदनाम करने की कुत्सित कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित की है जो सच को सामने लाएगी। अंत में उन्होंने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और ओलंपिक पदक विजेताओं को सीधे डिप्टी एसपी पद पर नियुक्ति देने की सरकारी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

शिक्षकों को मिली स्वास्थ्य सुरक्षा: सीएम योगी ने शुरू की कैशलेस चिकित्सा योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 08 जुलाई, 2026 को बाबा विश्वनाथ की पावन धरा वाराणसी से प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को ऐतिहासिक सौगातें दीं। उन्होंने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े 12 लाख शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और वार्डनों के लिए 05 लाख रुपये की वार्षिक 'मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना' का शानदार शुभारम्भ किया। इस कल्याणकारी योजना पर आने वाले लगभग 450 करोड़ रुपये का वार्षिक व्ययभार पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

इसी गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 01 करोड़ 10 लाख बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को नई उड़ान दी। उन्होंने विद्यार्थियों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता-मोजा और स्वेटर आदि की खरीद के लिए 1200 रुपये प्रति छात्र की दर से कुल 1,320 करोड़ रुपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में अन्तरित की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्वच्छ एवं हरित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया।

शिक्षकों और संविदाकर्मियों को एक अभूतपूर्व सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) के मध्य एक महत्वपूर्ण एमओयू का आदान-प्रदान भी किया गया। इसके तहत स्थायी शिक्षकों को 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस और 01 करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा, जबकि 10 हजार से अधिक मानदेय वाले संविदाकर्मियों को 30 से 80 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए 'ऐड ऑन कवर' की अनोखी सुविधा भी जोड़ी गई है।

अपने प्रेरणादायी संबोधन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है और इस पर किया गया निवेश कभी व्यर्थ नहीं जाता। उन्होंने 'ऑपरेशन कायाकल्प', 'निपुण भारत' और 'प्रोजेक्ट अलंकार' जैसी सफल योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह नकलमुक्त और पारदर्शी हो चुकी है। अंत में उन्होंने गुरुजनों से राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र महायज्ञ में समर्पित होकर बच्चों के भविष्य को गढ़ने और विद्यालयों में एक स्वच्छ, सुंदर तथा अनुशासित वातावरण बनाने का आह्वान किया।

शस्त्र और शास्त्र के संधान का केंद्र बनेगा चित्रकूट, ₹951 करोड़ की विकास परियोजनाओं से संवरेगी प्रभु श्रीराम की तपोभूमि

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिनांक 08 जुलाई, 2026 को जनपद चित्रकूट में 951 करोड़ रुपये की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। यह सभी परियोजनाएं विधानसभा चित्रकूट और मानिकपुर के चहुंमुखी विकास से संबंधित हैं।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक, प्रशस्ति पत्र, स्मार्ट फोन और नए आवासों की चाभियां भी वितरित कीं।जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चित्रकूट भारत की पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अनुपम प्रतीक है, जहां प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किया था।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पूर्व पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण इस पवित्र धरती के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन वर्तमान डबल इंजन सरकार ने चित्रकूट को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाया है। आज यहां की पावन मंदाकिनी नदी, महर्षि वाल्मीकि आश्रम और संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर का भव्य सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि चित्रकूट में नवनिर्मित एयरपोर्ट के माध्यम से शीघ्र ही दिल्ली और लखनऊ के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे इस पूरे क्षेत्र की लाइफ-लाइन बन चुका है।

रक्षा के क्षेत्र में प्रदेश की बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए नए समझौतों के तहत उत्तर प्रदेश में बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल का अब निर्यात भी किया जाएगा। चित्रकूट में स्थापित डिफेंस कॉरिडोर और रानीपुर टाइगर रिजर्व के माध्यम से क्षेत्र में बड़े निवेश, रोजगार और ईको-टूरिज्म के नए द्वार खुले हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के युवाओं को रोजगार देने और हर गरीब तक मुफ्त राशन, आवास, बिजली तथा आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चित्रकूट की आध्यात्मिक विरासत को संजोते हुए हमें भौतिक विकास की इस यात्रा में एकजुट होकर सहभागी बनना होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 जुलाई 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना (राज्य-योजना) क्रियान्वित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026' निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन, स्टार्टअप ईकोसिस्टम एवं सम्बन्धित पहलों के प्रोत्साहन हेतु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर नीति-2026' निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के मेडिकल कॉलेज के प्रस्तावित शिक्षण संकाय के निर्माण हेतु ग्राम पिण्डरा, परगना कोलअसला, तहसील पिण्डरा स्थित आ0नं0 3957 रकबा 17.563 में से रकबा 13 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के 100 बेड चिकित्सालय की स्थापना हेतु गीडा सेक्टर-09 (संस्थागत) स्थित भूखण्ड संख्या एएल-7 क्षेत्रफल 21427 वर्ग मीटर (5.249 एकड़) भूमि उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान आवंटन दर (टेलीस्कोपिक दर 8720 रुपये प्रति वर्ग मीटर) के स्थान पर रियायती दर 2,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4,28,54,000 रुपये तथा लोकेशनल चार्ज 60,70,500 रुपये सम्मिलित करने पर कुल प्रीमियम 4,89,24,500 रुपये के साथ ही, नियमानुसार अन्य शुल्क हेतु प्राविधान सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद मुरादाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के 100 शैय्या चिकित्सालय के लिए ग्राम हरथला, तहसील मुरादाबाद स्थित गाटा संख्या 1336/9.984 हेक्टेयर में से 2.025 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन कतिपय शर्तों के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम को करने तथा उक्त चिकित्सालय का संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 06 जुलाई 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग के अन्तर्गत कार्यरत होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक अधिकारियों एवं उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचारोपरान्त दी गयी संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने नगर निगम, गोरखपुर में 80 करोड़ रुपये तथा नगर निगम, मुरादाबाद में 50 करोड़ रुपये तक के म्युनिसिपल बॉण्ड निर्गत करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग एनहान्समेन्ट आदि के लिए धनराशि उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत कस्बा/नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर 'परशुरामपुरी' किये जाने तथा तद्सम्बन्धी अधिसूचना निर्गत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

- मंत्रिपरिषद ने जनपद रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु ग्राम पडेरा, परगना व तहसील सदर में जिला अधिकारी द्वारा चिन्हित 44.888 हेक्टेयर भूमि में से 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने 'उ0प्र0 अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022' में कतिपय विभागों के चिन्हित पद सम्मिलित करने हेतु संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

- मंत्रिपरिषद ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा वित्त आयोग के अन्तर्गत गठित वित्त प्रकोष्ठ में राज्य/मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय एवं राज्य/मण्डल/जनपद/विकास खण्ड स्तर की तकनीकी/प्रशासनिक/ सिविल/अन्य आवश्यकताओं हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवश्यक धनराशि के लिए तीनों स्तरों की पंचायतों को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का 1.05 प्रतिशत निदेशालय स्तर पर रोककर उपरोक्त व्यवस्थाओं में व्यय किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।